

विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। - जॉन्सन

आंकड़ों की सच्चाई से सरकार क्यों घबराई?

आज हम सरकार का मूल्यांकन केवल आरोपों–प्रत्यारोपों के आधार पर करने के बजाय, ठोस आंकड़ों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे, जिनमें से कई स्वयं सरकार के अपने ही आंकड़े हैं। हमें यह समझना होगा कि हम कितना ही स्वयं का गुणगान कर लें, आत्म मुग्ध हो जाएं, बड़े–बड़े विज्ञापन छपवा लें, हेडिंग लगावा लें, किंतु सच्चाई तो उन आंकड़ों से ही प्रकट होती है जो धरातल से एकत्रित किए जाते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जो हमें सच्चाई से रूबरू करते हैं।

गत कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी एवं सत्ताधारी दल के नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में बहुत सुधार हुआ है और भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अन्य देश भारत को बहुत आदर के साथ देखने लगे हैं।

किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय ताकत कितनी है या उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या दृष्टिकोण है, यह परिलक्षित होता है उस देश के पासपोर्ट की ताकत से। इस ताकत को नापा जाता है “ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स” से। इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग विश्व में 125वें स्थान पर है जबकि यह 2014 में 76वें तथा 2021 में 90वें स्थान पर थी। स्पष्ट है, भारतीय पासपोर्ट 2014 से लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीयों को लगभग सभी देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि घाना, नामीबिया और ट्यंज्यूनीशिया जैसे देशों को पासपोर्ट रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत की रैंकिंग खराब हो रही है और यहां के नागरिकों के लिए बाहर जाना अधिक कठिन हो रहा है। इससे यहां के लोगों के अवसर भी कम हुए हैं।

भारतीयों के न्यूजीलैंड जाने के वीजा प्रार्थना पत्रों में से लगभग 25 प्रतिशत अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के वीजा प्रार्थना पत्र में से 15 प्रतिशत खारिज हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि कई भारतीय दंपति अमेरिका में जाकर बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वे अमरीकी पासपोर्ट के साथ बड़े हों और उनके लिए भविष्य में विभिन्न देशों की यात्रा करना अधिक सुलभ और सुगम हो सके। पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व में 125 नंबर पर गिरकर,भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है, इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की समृद्धि का पैमाना केवल उसकी जीडीपी नहीं होता है क्योंकि जीडीपी तो जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 22000 रुपए प्रति माह है। यह भारत के सभी राज्यों में बहुत असमान है। जहां दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 50000 महीने है, वहीं बिहार में यह 7700 प्रतिमाह है। “अपर मिडल इनकम ग्रुप” में भारत के केवल पांच राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 450000 रुपए से अधिक है। ये राज्य हैं– दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। यदि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि से तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि भारत के राज्यों में ही कितनी असमानता है? जिन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया गया और जहां पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया, वहां पर निवेश भी हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े। कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि इन प्रदेशों के लिए देश की प्रगति का कोई अर्थ नहीं है।

जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया, उनकी समृद्धि भी बढ़ी। दिल्ली में “टोटल फर्टिलिटी रेट” केवल 1.9 है जबकि यही बिहार में 2.9 और उत्तर प्रदेश में 2.6 है। उल्लेखनीय है कि टी एफ् आर 2.1 होने पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जनसंख्या तेजी से बढ़ाने वाले राज्यों का प्रतिनिधिक संसद में परिसीमन के पश्चात अधिक हो सकता है, क्योंकि यह संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। यदि यही क्रम चलता रहा, तो शीघ्र ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए केवल उत्तर भारत के राज्यों के समर्थन के आधार पर ही बहुमत प्राप्त करके देश की सरकार बनाना संभव हो जाएगा। यह एक प्रक्रासे से उन राज्यों को सजा देने जैसा होगा जिन्होंने तेजी से प्रगति की तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया। क्या सरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती है कि देश में असमानता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है? न केवल यह, देश की संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ ही में परिवारों में सीमित होकर रह गया है। देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40 प्रतिशत है जबकि निचले 50 प्रतिशत के पास कुल 3 प्रतिशत है। यह प्रतिशत पहले से और घटता जा रहा है। अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यह बात कभी भी सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। केवल यह बताया जाता है कि कितनी जगह मेट्रो बन गई, चमकमाते स्टेडियम औय वुलेट ट्रेन बना दी गई।

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते हुए यह संभव नहीं है

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते हुए यह संभव नहीं है कि हम विकसित भारत या विश्व गुरु का तमगा लेकर घूमते रहें।

या 150 करोड़? सब कुछ केवल अनुमान पर आधारित है। किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी भी देश के लिए जगणपना ही योजनाएं बनाने का आधार होती है। यह देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विवरण स्पष्ट करती है। सरकार क्यों लगातार जगणपना करने से अब तक बचती रही है? यह सरकार आंकड़ों की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती करना जब कोविड में चुनाव कराए जा सकते हैं तो जगणपना क्यों नहीं?

आंकड़ों के पीछे के सच को स्वीकार करना ही सुधार का रास्ता हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे दरी के नीचे की गंदगी को नहीं देखने से सफाई नहीं हो जाती। सरकार को स्वीकार करना जरूरी से बचने की प्रवृत्ति देश के हित में नहीं है, न यह देश की योजना बनाने के लिए सही है। सरकार के पास जब तक वास्तविक आंकड़े ही नहीं होंगे तब तक यह कैसे तय होगा कि कहां कितने विद्यालय, अस्पताल या परिवहन के साधन चाहियें और कितने लोगों को नौकरी चाहिए? बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ रही है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पा रही है।

यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जगणपना के आंकड़ों को भी तोडमरोड कर इबुट्टा करना चाह रही है। प्रणकों को यह कहा जा रहा है कि वे परिवार के पास शौचालय होना मान लें, यदि शौचालय बना हुआ है, चाहे वह काम में नहीं आ रहा हो। इसी प्रकार कोई परिवार यदि पडोस के किसी शौचालय अथवा किसी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा है, तब भी यह माना जाएगा कि परिवार के पास शौचालय है। इस प्रकार से गलत आंकड़े इकट्ठे करके जो योजना बनेंगी, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह ही लगा रहेगा।

आंकड़ों को बारीकी से जब तक नहीं देखा जाएगा, तब तक असली स्थिति सामने नहीं आएगी। सरकार ने पहले यह कहा था कि 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, तो वास्तविकता यह थी कि उस समय भी देश में 3.30 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। जब तक घर के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं हो तब तक गांव के विद्युतीकृत होने का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जब तक स्वयं के परिवार में उपयोग में आने योग्य शौचालय नहीं हो तब तक परिवार को शौचालय वाले परिवार की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़ों की भी लगभग यही स्थिति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी बालक–बालिकाएं विद्यालय में नामांकित हैं। नामांकित होने से कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता, यह बात सरकार के अधिकारियों को पता है लेकिन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को मानना नहीं चाहते। आज भी 4.74 करोड़ बच्चे शिक्षा के आलोक से वंचित हो रहे हैं। इसी प्रकार लाखों व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होने के कारण कुपोषित भी हो रहे हैं तथा मौत का शिकार भी हो रहे हैं।

कुछ वर्षों पहले नेशनल सैपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के मुखिया को केवल इसलिए हटा दिया गया था कि उन्होंने सरकार के लिए असुविधाजनक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए थे। क्या आंकड़ों को रोकने से या उसके पीछे की सच्चाई को स्वीकार नहीं करने से वास्तविकता बदल जाएगी? आवश्यकता इस बात की है कि सच्चाई से घबराने और उससे दूर भागने के बजाय उनका सामना किया जाए और तदनुसार योजना बनाई जाए ताकि जो कमी है, उसको दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। जब उन कमियों को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर उनको दूर करने के लिए प्रयास करने की बात तो दूर की है।यदि इसी प्रकार से सरकार सच को स्वीकार करने से बचती रही और आंकड़े सार्वजनिक करने से भी बचती रही तो वह सही दिशा में योजनाएं बनाने का काम नहीं कर सकती।

बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संवैधानों को सरकार, भारत के विरुद्ध साजिश बता कर उन आंकड़ों को नकारने का प्रयास करती है। होना तो यह चाहिए कि यदि सरकार को ये आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अपने आंकड़े एकत्र करें और उन्हें सार्वजनिक करें ताकि लोग पता कर सकें कि सरकार के आंकड़े कितने सही हैं? सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, यही तो समस्या है।

आशा की जानी चाहिए कि जगणपना में लगे प्रणकों को ईमानदारी से वास्तविक स्थिति पता करने के लिए कहा जाएगा न कि बनावटी आंकड़े एकत्र करने के लिए।

ऐसा होने के बाद ही सरकार देशवासियों के लिए सही प्रकार की योजनाएं बनाने में सक्षम हो पाएगी। तब, शायद असमानता को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और भारत की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय जगत में बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठाए जा सकेंगे। कुल मिलाकर, आवश्यकता इसी बात की है कि सरकार सच्चाई का सामना करने का साहस करे। यही उसके और देशवासियों के हित में है।

—अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र भागवत

(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अनुराग शुक्ला

बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है।

“**कह कबीर कैसे निभे बेर-केर के संग**

वे डोलत मन आपने, उनके फाटत अंग”।

वैसे तो कबीरदास जी ने कई सौ साल पहले एक ऐसी बात लिखी थी जो शत प्रतिशत सही है पर राजनीति में सोलह आने सच्ची बात भी हमेशा पूरी तरह सच नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ भी आने को तैयार है पर सियासी तौर पर एक–दूसरे

को तौल भी रहे है। गठबंधन की तरफ जाते भी दिख रहे हैं और रास्ते में दोनों पाटियों के बयानों के स्पीड ब्रेकर भी कई सारे हैं।

हाल में ये ही बात तब और बढ़ी जब उत्तर प्रदेश के नए नए प्रभारी बने राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ आते ही सियासी बयान का गोला दाग दिया। उन्होंने हिस्सेदारी बराबरी की होने की बात की। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने उनके बयान को राजनीतिक पहचान बनाने कोशिश कहकर अनसुना कर दिया। वैसे राजेंद्र पाल गौतम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासत के कई पहलू हैं। राजेंद्र गौतम वो नेता हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के सांसद तनुज पुनिया के साथ मायावती के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि मायावती ने उन्हें मिलने नहीं दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। उस दौरान भी चर्चा उठी थी कि राजेंद्र और तनुज गठबंधन का प्रस्ताव लेकर मायावती के पास पहुंचे थे। अब राजेंद्र गौतम को ही यूपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है।

पहले कारण बताओ नोटिस और कुछ ही दिन में यूपी जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनना संकेत दे रहा है कि गौतम का ये बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने की कवायद भर नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने बराबरी का हक मांगा है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सभी सीटों पर तैयारी और बराबरी की बात कर चुके हैं। उन्होंने तल्लू अंदाज में कहा था हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांगते हैं कि वे हमें कितनी सीट देंगे, बराबरी पर बात होगी। समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांठोस की तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए। दअसल बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। सीटों के समान बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा करके वह संकेत दे रही है कि वह अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जूनियर पार्टनर के तौर पर अपनी पहचान बदलना चाहती है। पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद संगठन को मजबूत बना रही है और बराबरी का दर्जा मांग रही है वैसे भी यूपी कांग्रेस का गढ़ रहा है।

ये बात और है कि आज उसके पास सियासी जमीन नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो 170 सीटों तक की मांग कर सकती है जबकि सपा 60–80 सीटें देने का मन बना रही है। सपा के पास पीडीए का समीकरण और संगठन की ताकत है तो कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्ट का

भक्ति संगीत के शिखर पुरुष भजन गायक “रामचंद्र गोयल”

गाये जाने वाले भजनों को सुनते तो भाव विभोर हो जाते। मन करता, काश वे भी इतना सुरीला भजन गा पाते। मां के कारण बचपन से ही भजन के प्रति गहरा लगाव हो गया। धीरे–धीरे गांव की स्कूल में भजन गाने शुरू किए। लोगों से सराहना मिली तो भजन के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में पूरी करने के बाद जोधपुर में आ गए। सम्पूर्ण शिक्षा पूरी कर गृहस्थी चलाने के लिए बिजली विभाग में बाबू की नौकरी कर ली। इसके साथ ही सुबह–शाम भक्ति संगीत की साधना में लगे रहे। भारतीय संगीत के पंडित हुकमदास जी व वी.एन.क्षीरसागर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर संगीत विषाद की डिग्री ली। तड़के चार बजे उठ कर संगीत की साधना में जुट जाते।

धीरे–धीरे भक्ति संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली। जब वे मंच से भजनों की सरिता बहाते तो सुनने वाले झूम उठते। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। अपनी माताजी के बाद उल्हासनगर (बंबई) की पूज्य माताजी हरवंश नांगिया के सान्निध्य एवं प्रेरणा से आपके मन में संगीत एवं भजनों के प्रति गहरी रुचि जागृत हुई, जिसने आगे चलकर आपके जीवन को पूर्णत: भक्ति संगीत की साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। राजीव गांधी के निधन के बाद उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में इनका भक्ति संगीत का कार्यक्रम रखा गया। इस भक्ति संगीत कार्यक्रम में कई केन्द्रीय मंत्री तथा प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ देश की सभी प्रमुख हस्तियाँ मौजूद थीं। उस दिन उन्होंने जोधपुर का जो मान बढ़ाया, उसकी धमक आज भी दिल्ली की फिजाओं में

लेबल लेकर चल रही है। मायावती के घर जाने की कोशिश कर कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि यूपी में सिर्फ सपा के भरोसे नहीं है।

सपा को पता है कि कांग्रेस के नेता चाहे जो बोल लें आखिरी फैसला हाईकमान लेगा। इसलिए अखिलेश ने चुपी साध ली है। उन्हें पता है कि बातचीत की टेबल पर आंकड़े उनके पक्ष में हैं। कांग्रेस यूपी में 37 साल से सत्ता में नहीं है। हर चुनाव में उसकी हालत पतली ही होती गयी है। यूपी में 1989 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो 425 सीटों में से सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाई। फिर 1991 में 419 में से सिर्फ 46, 1993 में 422 में से सिर्फ 28, 1996 में 424 में से सिर्फ 33, 2002 में 403 में से सिर्फ 25, 2007 में 403 में से सिर्फ 22, 2012 में 403 में सिर्फ 28, 2017 में 403 में सिर्फ सात और 2022 में 403 में से सिर्फ दो सीटें ही जीत सकी है। वो भी ऐसी जो नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर जीती थीं। ऐसे में अखिलेश चुप है बेवजह के बयान नहीं देना चाहता। सीट की जगह जित्ताऊ प्रत्याशी की बात करते हैं।

यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिनों में उसकी दलित, पिछड़ा और ब्राह्मणों का सपोर्ट था पर ये कहानी पुरानी है। नई कहानी है कि पिछड़ा और दलित वोटों ने अखिलेश की विस्तार चाहते हैं तभी तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। वहीं

कांग्रेस को भी अपने परंपरागत दलित वोटर तक पहुंचना है। कांग्रेस का विस्तार सपा के वोटों के मूल्य पर होगा। पर इस समय सपा को चिंता वोट की नहीं 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा की है। इससे भी बढ़कर यूपी में 2024 की सफलता को अगर सपा दोहराती है तो इंडी गठबंधन में अखिलेश का रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। ये बात कांग्रेस को भी पता है। राहुल गांधी आम तौर पर अपने से बड़ा किसी और का सियासी कद बढ़ाश्त नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि बराबरी के बंटवारे की बात हो रही है।

सपा गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, ऐसे में ये भी हो सकता है कि सपा 80 सीटें कांग्रेस को दे और 20–30 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपने सिंबल पर उतार दे। अखिलेश को ये फार्मूला बहुत भाता है। सपा संयमित है क्योंकि उसकी लड़ाई अभी भाजपा से है, कांग्रेस व्याकुल है क्योंकि उसको यूपी की सियासी जमीन चाहिए। अभी ये तो तय माना जा रहा है कि दोनों पाटियां मिलकर ही चुनाव मे ताल ठोकेंगी पर दोनों को पता है कि–

मिले हैं हाथ तो अब साथ चलना लाज़मी है, मगर यहाँ कोई भी समझौता मुफ्त का नहीं होता।

—अनुराग शुक्ला, (लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)



रामचंद्र गोयल

अपने भजनों व रामचरित मानस को स्वर दिया। स्वामी जी के अलावा देश के नामी–गिरामी जी के व भजन गायकों से गहरा सम्पर्क रहा जिनमें ईश्वरानंद जी, सत्यमित्रानंद जी, अभयगाम जी महाराज प्रमुख हैं।

राष्ट्रदूत संवाददाता से बातचीत करते रामचन्द्र गोयल कहते हैं उन पर सर्वाधिक प्रभाव संतों के जीवन से पड़ा है। प्रोत्साहन के बारे में पूछने पर कहते हैं कि भगवान का प्रोत्साहन ही मुख्य रूप से रहा। रामचंद्र गोयल अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय अपने आराध्य भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तथा अपनी माँ एवं स्वामी रामसुखदास जी महाराज की असीम कृपा को देते हैं। उनका मानना है कि इन्हीं की कृपा से उनका मानव जीवन सफल हुआ। नब्बे वर्ष की उम्र में भी पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी है। आज भी वे स्वाध्याय करते हैं। गोयल खुद भजन लिखते भी हैं। अब तक करीब सौ भजन लिख चुके हैं।

–मिश्रीलाल पंवार, लेखक जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की मिल रही राहत

बूंदी, (निर्सं)। आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में शुरू किए गए ग्रामीण सेवा शिविरों से ग्रामीणों की रितैर राहत मिल रही है। ग्राम पंचायत घाट का बनाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दो किसानों की कृषि भूमि के बंटवारे का वकी पुराना मामला मौके पर ही हल कर दिया गया। ग्राम बलदेवपुरा निवासी किसान ओमप्रकाश

और मानसिंह अपनी 1.73 हेक्टेयर कृषि भूमि के खाता विभाजन को लेकर काफी समय से परेशान थे। राजस्व रिकार्ड में नाम दफ्त करवाने और भूमि के स्पष्ट बंटवारे के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ग्राम पंचायत घाट का बनाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर मौजूद

तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य